

प्रेस विज्ञप्ति

iFOREST ने जारी की स्टबल बर्निंग स्टेटस रिपोर्ट 2025: पराली जलाने के समय में बदलाव के चलते सरकारी डेटा में 90% से अधिक बड़े खेतों की आग दर्ज ही नहीं; पंजाब और हरियाणा में जली हुई फसल का क्षेत्र 25–35% कम

नई दिल्ली, 8 दिसंबर 2025: इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) द्वारा आज जारी की गई एक नई रिपोर्ट, भारत के पराली जलाने की निगरानी में मौजूद एक गंभीर कमी को उजागर करती है।

स्टबल बर्निंग स्टेटस रिपोर्ट 2025 दिखाती है कि जहाँ सरकारी डेटा पंजाब और हरियाणा में खेतों में लगाई जाने वाली आग में 90% की भारी कमी का दावा करता है, यह कमी दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (CREAMS) द्वारा संचालित मौजूदा निगरानी प्रणाली की आपूर्ति का परिणाम है।

रिपोर्ट में भारत की पहली मल्टी-सैटेलाइट, मल्टी-सेंसर असेसमेंट पेश की गई है, जिसमें MODIS (टेरा और एक्वा उपग्रह), VIIRS (सुओमी-NPP उपग्रह), सेंटिनल-2 मल्टीस्पेक्ट्रल इंडेक्स (MSI) बर्न-एरिया मैपिंग और मेघा-ट्रोपिक्स-8 व 9 पर लगे स्पिनिंग एन्हांस्ड विजिबल एंड इन्फ्रारेड इमेजर (SEVIRI) के 15 मिनट के अंतराल पर लिए गए भूस्थिर अवलोकनों को जोड़ा गया है।

आज एक राष्ट्रीय वेबिनार में जारी इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि CREAMS की निगरानी पद्धति—जो मुख्यतः पोलर-ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स (MODIS/VIIRS) पर निर्भर है जो भारत के ऊपर केवल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच गुजरते हैं—पिछले वर्षों में दोपहर बाद और शाम को तेजी से बढ़े बड़े खेतों में लगाई जाने वाली आग को पकड़ने में विफल हो रही है। SEVIRI के उच्च-आवृत्ति अवलोकनों से iFOREST ने पाया कि:

- पंजाब में, 2024 और 2025 में 90% से अधिक बड़े खेतों में आग 3:00 बजे के बाद लगाई गई, जबकि 2021 में यह आँकड़ा सिर्फ 3% था।
- हरियाणा में, 2019 से ही अधिकांश बड़े खेतों में आग 3:00 बजे के बाद लगाई जा रही है — यानी वर्षों से आँकड़ों में कमी दर्ज हो रही है।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि ऐसे डेटा अंतर से वायु-गुणवत्ता नीति निर्माण के लिए आवश्यक साक्ष्यों का आधार कमजोर हो रहा है।

वेबिनार में विवरण साझा करते हुए iFOREST के सीईओ चंद्र भूषण ने कहा: “हमारा विश्लेषण निर्विवाद रूप से दिखाता है कि भारत की मौजूदा पराली निगरानी प्रणाली जमीनी वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती। किसान अब खेत जलाना दोपहर बाद के समय कर रहे हैं, जबकि हमारी निगरानी प्रणाली केवल सीमित समय—10:30 बजे से 1:30 बजे तक—सक्रिय आग को पकड़ती है। इसका परिणाम आग, उत्सर्जन और दिल्ली की वायु प्रदूषण में उनके योगदान का भारी कम आकलन है। हमें तत्काल प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।”

इसके साथ ही iFOREST की जली हुई फसल क्षेत्र की मैपिंग वास्तविक प्रगति की ओर इशारा करती है।

सेंटिनल-2	बर्न्ट-एरिया	विश्लेषण	दर्शाता	है:
-----------	--------------	----------	---------	-----

- पंजाब: खरीफ सीज़न में जली हुई फसल का क्षेत्र 2022 में चरम 31,447 वर्ग किमी से घटकर 2025 में लगभग 20,000 वर्ग किमी रह गया — यानी 37% की कमी।
- हरियाणा: 2019 में 11,633 वर्ग किमी के चरम से घटकर 2025 में 8,812 वर्ग किमी — 25% की कमी, हालांकि रुझान स्थिर नहीं है।

इन निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए चंद्र भूषण ने कहा: “जला हुआ क्षेत्र पराली जलाने की वास्तविक स्थिति को अधिक सटीक दिखाता है। हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि पंजाब और हरियाणा ने 25–35% तक कमी हासिल की है, जो अच्छी बात है और बताता है कि इन-सीटू और एक्स-सीटू स्टबल-मैनेजमेंट तकनीकों को अपनाया जा रहा है। लेकिन यह आत्मसंतोष का समय नहीं है। 2025 में भी, पंजाब और हरियाणा में लगभग 30,000 वर्ग किमी धान के खेत जलाए गए — जो दिल्ली-एनसीआर और पूरे इंडो-गैंगेटिक क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बिगाड़ने का बड़ा स्रोत है।”

रिपोर्ट तुरंत सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता पर जोर देती है, जिनमें शामिल हैं:

- संशोधित निगरानी प्रोटोकॉल: CREAMS को केवल एक्टिव फायर काउंट ही नहीं, बल्कि बर्न्ट-एरिया डेटा भी जारी करना शुरू करना चाहिए, ताकि अधिक सटीक राष्ट्रीय तस्वीर मिल सके।

- अपडेटेड एयर-क्वालिटी फोरकास्टिंग मॉडल्स: दिल्ली की वायु-गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) की पद्धति को संशोधित कर पराली के योगदान का सही आकलन किया जाना चाहिए।

नीतिगत रोडमैप पर चर्चा करते हुए iFOREST के प्रोग्राम लीड ईशान कोचर ने जोर दिया: “हम जिसे सही तरीके से माप नहीं पाते, उसे प्रबंधित भी नहीं कर सकते। नीति-निर्माण अभी अधूरी सूचनाओं के आधार पर हो रहा है। इंडो—गैंगेटिक प्लेन में पराली जलाने की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को निगरानी प्रोटोकॉल में तुरंत सुधार करना होगा — जिसमें बर्न्ट-एरिया मैपिंग और भूस्थिर डेटा को शामिल करना आवश्यक है। साथ ही हमें पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे उभरते हॉटस्पॉट्स पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।”

मीडिया संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क करें:
श्रिया मोहन
कम्युनिकेशन्स लीड, iFOREST
+91 7042144726 | shriya@iforest.global